किए और अभ्रक के संसाधन की व्यवस्था करने हेतु धन खर्च किया और उन्होंने माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन को करोड़ों रुपये दिए लेकिन उक्त निगम ने 76.00 लाख रुपये का अपव्यय करने के बाद केवल 24.00 लाख रुपये ही आय दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करवाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): (क) संसाधित अभ्रक तथा अभ्रक स्क्रेप का निर्यात भारतीय अभ्रक व्यापार निगम (मिटक) के माध्यम से सरणीकृत है मिटकों ने निगम द्वारा निर्धारित कीमतों के अनुसार मिटकों की ओर से सामान्य मुद्रा क्षेत्र से आर्डर प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व प्राइवेट अभ्रक निर्यातकों को मिटको के एजेंटों को बतौर कार्य करने की सुविधा प्रदान की है, तथापि प्राइवेट निर्यातकों को अपने ही स्रोतों से 50% आर्डरों की व्यवस्था करने के लिए अनुमति है। 1985-86 में संसाधित अभ्रक के कुल निर्यात 24.14 करोड़ रु. के हुए।

(ख) से (घ) 1985-86 के दौरान निर्यात के लिए कुल आर्डरों में से 69% आर्डर मिटको द्वारा स्वयं प्राप्त किए गए तथा 31% आर्डर प्राइवेट निर्यातकों द्वारा लाए गए वर्ष 1985-86 के दौरान प्राइवेट निर्यातकों द्वारा व्यवस्थित बैक-टू-बैक संविदा के संघ प्रभारों से 18.60 लाख रु. की आय हुई। किसी भी प्रकार की जांच करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इस संबंध में कंपनी के लेखाओं की संबंधित कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा की जाती है।

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम

2782. **श्री कैलाश पति मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम की स्थापना 1972 में की गई थी ताकि वह 2000 छोटे डीलरों से संसाधित अभ्रक निर्यात के लिए खरीदने को सुनिश्चित करें जिससे इन डीलरों और उनके साथ काम कर रहे श्रमिकों का जीवन-यापन होता रहे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम माफिया गैंग को, जिसमें लगभग 200-300 ऐसे डीलर शामिल हैं जिनके पास जाली लाइसेंस हैं और जो सारे लाभों को हड़प रहे हैं; सहायता देता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): (क) से (ग) अभ्रक व्यापार के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के संरक्षण तथा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से आरंभ में 24 जनवरी, 1972 से संसाधित अभ्रक का निर्यात भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लि. की मार्फत सरणीकृत किया गया। बाद में 18 जून, 1974 को अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) की स्थापना की गई और उसने इन कार्यों को अपने अधिकार में लिया। निर्यात आर्डरों की व्यवस्था करने के लिए मिटको वैध लाइसेंस धारक पंजीकृत व्यापारियों से, जो अपने माल की निविदा देने में स्वतंत्र हैं, माल प्राप्त करता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी अभ्रक व्यापारी लाइसेंसों के आधार पर मिटको व्यापारियों का पंजीकरण करता है। निर्यात के लिए माल प्राप्त करते समय छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाती है।

Banking facilities enjoyed by Thapar Group from Oriental Bank of Commerce

2783. SHRI CHIMANBHAI MEHTA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Oriental Bank of Commerce was owned and controlled by Thapar group prior to its nationalisation;

(b) what are the banking facilities being enjoyed by the Thapar Group from this Bank at present; and

(c) whether the borrowings of Thapar Group from this Bank are adequately secured as per the norms of the banking sector or any exceptions are made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI) : (a) Prior to its nationalisation, the majority share-holding

of the Oriental Bank of Commerce was held by Thapar Group.

(b) and (c) The Oriental Bank of Commerce has reported that it has sanctioned facilities to 12 companies of the Thapar Group aggregating Rs. 13.01 crores. It has also reported that the facilities are adequately secured and are as per the lending norms of the bank.

Raids to detect black money

2784. SHRI VIRENDRA VERMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what are the details of the raids conducted at the premises of high ranking Government and public sector officials to unearth black money since the beginning of 1986 till date and what is the outcome thereof; and

(b) what action has been taken/proposed to be taken by Government in cases where unaccounted wealth has been detected ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Fee concession to disabled persons for recruitment of Probationary Officers in Banks

2785. SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Banking Services Recruitment Board has discontinued the concession in fees given to the disabled persons for recruitment of Probationary Officers; and

(b) whether Government propose to exempt the disabled from payment of fees in "The Decade for Disabled" sponsored by the United Nations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI) : (a) Since there is no reservation for physically handicapped persons in recruitment to officers cadre, the concession in application fee, given earlier, has been discontinued. The physically handicapped persons, however, continue to be exempted from the payment of application/examination fees for recruitment to the clerical and subordinate cadre posts.

(b) The Ministry of Welfare has advised that there is no such proposal under consideration of Government.

Installation of computers in the Income Tax Department

2786. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what are the names of the places where computers have been installed in the Income Tax Department;

(b) what are the names of the places where computers are likely to be installed in the near future;

(c) what type of work is being handled/will be handled with the help of the computers; and

(d) whether the installation of computers will have any adverse effect on the promotional chances of the employees and if so, to what extent ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI) : (a) In the Income Tax Department, a computer has been installed at Madras and a Micro Processor in Delhi.

(b) Computers are likely to be installed in the near future at the Headquarters of the following Commissioners of Income Tax, namely :

Ahmedabad, Amritsar, Agra, Allahabad, Bangalore, Bombay, Baroda, Bhopal, Calcutta, Cochin, Coimbatore, Delhi, Jabalpur, Jullundur, Jodhpur, Jaipur, Hyderabad, Kanpur, Kolhapur, Lucknow, Madurai, Meerut, Nagpur, Nasik, Patna, Pune, Patiala, Rohtak, Rajkot, Ranchi, Bhubaneshwar, Surat and Shillong.

(c) The following type of work is being handled/will be handled with the help of computer :—

(i) Processing of Tax Returns under Summary Scheme;

(ii) Processing of Income Tax Challans;

(iii) Allotment of Permanent Account Number;